Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)
E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

भूटान एवं नेपाल में राजनीतिक दल तथा दबाव समूह

राकेश कुमार शर्मा

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

प्रस्तावना

आधुनिक विश्व समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मांग के साथ आरंभ होता है। स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग 17वीं शताब्दी में उभरकर आई तथा 18 वीं शताब्दी में समानता की मांग हुई। आज दुनिया में लोकतंत्र एक सर्वोच्च आदर्श के रूप में प्रतिस्थापित हो चुका है। एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य और सरकार से होता है आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रकार के शासन को श्रेष्ठतम रूप में देखा जाता है।

राजनीतिक प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय राजनीतिक एवं कानूनी निर्णयों को प्रभावित करने या अभीष्ट रूप देने से से है। राजनीतिक प्रक्रिया में शासन तो सम्मिलित होता ही है, किन्तु इसके अतिरिक्त अनेक औपचारिक और गैर–सरकारी तत्व भी आ जाते है,

जो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में शासन तंत्र को प्रभावित करते है–यथा सामाजिक एवं आर्थिक संगठन, उनकी विचारधाराएँ राजनीतिक शैली, राजनीतिक दलों, हित समूहों एवं नेतृत्व की संरचना, जनमत इत्यादि। इस प्रकार किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया उसके शासन–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इनसे सम्बन्धित तथा इन पर प्रभाव डालने वाले पूर्व–वर्णित कारको से मिलकर बनती है। ये सभी कारक उस देश के समाज की राजनीति का पर्यावरण बनाते हैं, उसकी राजनीतिक प्रक्रिया की आधारभूत समस्याओं, साधनों अभिवृत्तियों, समूहों, राजनीतिक गठबन्धनों आदि का ज्ञान कराते है तथा ये सभी मिलकर सरकार के निर्णयो को प्रभावित करते हैं।

उपर्युक्त आधारभूत पहलुओं और शासन से मिलकर राजनीतिक प्रक्रिया किसी भी समाज की राजनीति को गतिमान बनाती है। राजनीतिक प्रक्रिया के इन आधार भूत पहलुओं से उठने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैचारिक दावे तथा उनके समर्थन सदैव अधिकारियों और शासन के अंगों के समक्ष इस मांग के साथ रखे जाते हैं कि उन्हें सार्वजनिक नीति में परिवर्तित किया जाये, राजनीतिक दल, हित अथवा दबाव समूह तथा राजनीतिक नेता ऐसे दावों को सरकार के समक्ष रखते हैं। इस प्रकार ये सभी तन्त्र राजनीतिक प्रक्रिया के भीतर क्रियाशील अभिकर्त्ताओं का कार्य करते हैं। व्यवहार में राजनीति के ये गतिशील कारक राजनीतिक प्रक्रिया के आधार तथा शासन की नीति निर्धारण करने वाले अंगों के बीच की खाई को पाटते हैं।

आधुनिक युग में राजनीतिक प्रक्रिया के कुछ अनौपचारिक अंग अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाने लगे हैं। इनमें प्रमुख रूप से राजनीतक दल, दबाब तथा हित समूह एवं जनमत सम्मिलित हैं।

यद्यपि कुछ समय पूर्व तक किसी देश की शासन प्रणाली के अध्ययन में प्रवृत्ति यह थी कि शासन के औपचारिक संगठन एवं संवैधानिक व्यवस्था पर अत्यधिक जोर दिया जाता था परिणामस्वरूप अनौपचारिक संगठनों जैसे राजनीतिक दलों के आन्तरिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परन्तु तुलनात्मक विश्लेषण के विकास के परिणामस्वरूप औपचारिक व्यवस्था तथा अनौपचारिक प्रक्रिया के बीच के अन्तर में काफी कमी आ गयी है। आज अनौपचारिक प्रक्रिया के कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गये है। वस्तुतः औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाओं के बीच सम्बन्धजोड़कर ही हम किसी देश विशेष की शासन पद्धति पर पूर्ण दृष्टि डाल सकते हैं। इस प्रकार, इन अनौपचारिक संस्थाओं जैसे हित, सामाजिक वर्ग समूह, राजनीतिक दलों, जनमत इत्यादि पर विस्तृत चर्चा करना आवश्यक है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि एक ओर हित समूह होते हैं दूसरी और शासन। उनके बीच सम्बन्ध जोड़ने वाली

कड़ी राजनीतिक दल की होती हैं। अतः हम राजनीतिक प्रक्रिया को इन तीन शब्दों के रूप में भली प्रकार समझ सकते हैं– हित, दल और शासन।

राजनीतिक दल

किसी भी समाज की राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का विशेष स्थान होता है, चाहे वह सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल। इसके अतिरिक्त बहुत सारे छोटे–छोटे दल, दबाव गुट, विचार–मंच, जनान्दोलन इत्यादि भी अपने ढंग से देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ उस संगठन से है, जो विशिष्ट राजनीतिक विचारों एवं कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। इसके सदस्य समाज की समस्त या विशिष्ठ समस्याओं से सम्बन्ध रखते हैं तथा उन समस्याओं के समाधान के बारे में कमोवेश एक ढंग से सोचते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रमुख मान्य नेता होते हैं, जो अपने समर्थकों, मतदाताओं तथा जनसाधारण के हृदय में स्थान बनाकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। वे सार्वजनिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में निर्णायक या प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए चुनाव लड़ते हैं या अपनी पसन्द के उम्मीदवारों को सहायता एवं समर्थन देते हैं। वस्तुतरू दलीय राजनीति उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। नेपाल में दलीय व्यवस्था (System of Political Parties in Nepal) नेपाल की राजनीति में दलीय व्यवस्था का आरम्भ 1940 के उत्तरार्ध तथा 1950 के पूवार्ध में हुआ। इस कालक्रम के मध्य अस्तित्व में आने वाले प्रायः सभी राजनीतिक दलों का स्वरूप एवं नीतियाँ बहुत सीमा तक नेपाल के पड़ोसी राष्ट्र भारत के राजनीतिक दलों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकीं। अतरू जहाँ एक ओर भारत के राजनीतिक दल ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए संघर्षरत थे, नेपाल के राजनीतिक दल राणावंश के निरंकुश शासन को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों ही देशों के राजनीतिक दलों के समक्ष अपने–अपने देशों में निरंकुश शासन–सत्ता की समाप्ति का स्थान लक्ष्य था। अतः जहाँ भारत को ब्रिटिश आधिपत्य से 1947 में स्वाधीनता प्राप्त हुई वहीं नेपाल 1950–51 की सशस्त्र जन–क्रान्ति के द्वारा राणा वंश का शासन समाप्त हो गया। राणावंश के शासन की समाप्ति के पश्चात से लेकर सन् 1960 में राजा महेन्द्र द्वारा सत्ता सँभालने के पूर्व तक नेपाल की राजनीति में छोटे–छोटे अनेक राजनीतिक दल सक्रिय थे। इन छोटे–छोटे राजनीतिक दलों का अस्तित्व व्यक्तिगत उच्च आकांक्षा वाले राजनीतिज्ञों के व्यक्तित्व पर केन्द्रित था।

यही कारण है कि 1960 में राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध की घोषणा के उपरान्त नेपाल की राजनीति में उन सभी छोटे मोटे बहुसंख्यक राजनीतिक दलों का तिरोधान हो गया, जो व्यक्तिवादी राजनीति के कारण अस्तित्व में आये थे। इन राजनीतिक दलों में नेपाल प्रजापरिषद, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद, नेपाल तराई कांग्रेस इत्यादि प्रमुख तववच से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त नेपाल राजनीतिक प्रक्रिया के प्रमुख राजनीतिक दलों के इतिहास तथा कार्यक्रमों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

1. नेपाल प्रजापरिषद नेपाल की सबसे प्राचीन राजनीतक संस्था नेपाल प्रजापरिषद की स्थापना सन् 1936 में काठमाण्डु में की गई।
2. नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा दल–नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद की स्थापना सन् 1953 में मृगेन्द्र शमशेर तथा रणधीर सुब्बा ने मिलकर किया था। इस राजनीतिक दल का प्रमुख लक्ष्य नेपाल में राष्ट्रवाद का प्रचार तथा नेपाली कांग्रेस का विरोध करना मात्र था।
3. नेपाल तराई कांग्रेस–नेपाल तराई कांग्रेस दल की स्थापना बलदेवदास यादव, कुलानन्द झा तथा भद्रकाली मित्र ने अगस्त सन् 1953 में की थी। इस दल का उददेश्य तराई प्रदेश को एक पृथक राज्य का स्वरूप प्रदान करना
4. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 15 सितम्बर 1949 को कलकता में की गयी थी। इसके संस्थापकों में कामरेड पुष्पलाल, नारायण विलास, नरबहादुर एवं दुर्गा देवी प्रमुख थी। इसकी स्थापना के समय नेपाल में स्वेच्छाचारी राणा शासन विद्यमान था, जिसके अन्तर्गत किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि या पार्टी का संचालन करना सम्भव नहीं था। कामरेड पुष्प लाल की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया जिसका उदेश्य नेपाली सर्वहारा वर्ग कार्यकर्ताओं, किसानों, स्त्रियों, विद्यार्थियों, बौद्धिक जनों, राष्ट्रीय पूंजीपतियों, व्यापारियों, कामगारो, मजदूरों के हितों की रक्षा करना था।
5. नेपाली कांग्रेस–नेपाली कांग्रेस अभी तक नेपाल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं वर्तमान में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है।थे। नेपाल के भीतर तेजी से परिवर्तित होने वाले राजनीतिक परिदृश्य में एक सशक्त राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को और अधिक मुखरित किया। प्रधानमंत्री मोहन शमशेर की दमनकारी नीतियों के चलते नेपाली जनता में रोष की भावना घर कर गई परिणामस्वरूप, नेपाल के भीतर के घटनाक्रम में तीनों राजनीतिक दलों को

पुनर्विचार के लिए प्रोत्साहित किया। यद्यपि रेगमी के नेतृत्व में चलने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस ने विलय के मुद्दे से अपने को पृथक् रखा फिर भी वी०पी० कोइराला के नेतृत्व में चलने वाली नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सुवर्ण शमशेर एवं महावीर शमशेर के नेतृत्व में चलने वाली प्रजातांत्रिक कांग्रेस में आपस में विलय का निश्चय किया। इसकेप्रक्रिया पीछे दोनों ही राजनीतिक दलों की अपनी–अपनी मजबूरियाँ थीं, क्योंकि जहाँ प्रजातांत्रिक कांग्रेस के नेताओं को जनता के समर्थन की आवश्यकता थी, वहीं दूसरी ओर नेपाली काग्रेस को अपनी वित्तीय समस्याओं को सुलझाना आवश्यक था। राष्ट्रीय कांग्रेस के पास जन समर्थन तो अवश्य था, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए धन की कमी आड़े आ रही थी। इसी प्रकार, नेपाली प्रजातांत्रिक कांग्रेस के पास धन तो बहुत था, लेकिन जन–समर्थन का अभाव था। अतः दोनों पार्टियों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। अतः दोनों दलों के नेताओं ने एक होकर एक सशक्त राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया। इन दोनों दलों के विलय की घोषणा 9 अप्रैल, 1950 को कलकत्ता में आयोजित सम्मेलन में की गई। इस विलय के परिणामस्वरूप जो नया दल अस्तित्व में आया उसे नेपाली कांग्रेस का नाम दिया गया। एम. पी. कोइराला इस नये दल के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर नेपाली कांग्रेस ने अपना ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया। इस युगान्तरकारी घोषणा पत्र में सभी नेपाली जनों से नेपाल की सारी अवनति के मूल कारण राणा शासन की तानाशाही एवं जुल्मी शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने तथा उसे उखाड़ फेकनेष का आहवान किया गया था। इसके साथ ही साथ इस नये दल ने राणा शासन के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र के अधीन प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना को अपना राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया।

जबकि भूटान में अभी प्रमुख रूप से 4 राजनीतिक दल ही भूटान निर्वाचन आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है

1. **पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी**–स्थापना 1 सितंबर 2007 को की गई थी यह भूटान का सबसे पहला राजनीतिक दल है।
2. **द्रुक फुनसम त्शोगपा (डी.पी.टी)**–स्थापना 2 अक्टूबर, 2007 को की गई थी।
3. **द्रुक न्यामरूप त्शोंगपा**–स्थापना 2013 में की गई थी
4. **भूटान कूएन–न्याम पार्टी**–स्थापना 2013 में की गई थी

24 मार्च, 2008 को भूटान के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संसद के लिये 47 सदस्यों का चुनाव शान्ति पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ और 25 मार्च को परिणाम की घोषणा कर दी गई। चुनाव में सिर्फ दो दल ही आमने–सामने थे। एक दल का नाम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे भूटान के सर्वप्रथम राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने का श्रेय जाता है।

संस्थापक त्शेरिंग तोबगे एक भूटानी राजनीतिज्ञ हैं,जो जुलाई 2013 से अगस्त 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री रहे थे और दूसरा दल द्रुक फुनसम त्शोगपा (डी.पी.टी)। उल्लेखनीय है कि जिस समय दलीय व्यवस्था के अन्तर्गत दलों का पंजीकरण हो रहा था उस समय चार दल आमने–सामने संभावित दिखाई दे रहे थे। परन्तु या तो प्रशासनिक नीतियों के आधार पर या अन्य दो दल जिनको पंजीकरण के योग्य नहीं समझा गया चुनावी मैदान से हटा दिये अन्तिम रूप से केवल दो दलों का ही पंजीकरण स्वीकार किया गया जिन अन्य दो दलों का पंजीकरण नहीं हो सका यहाँ स्पष्टीकरण देना सहज नहीं है। कुल मिलाकार यही समझा जाना चाहिये कि भूटान में सिर्फ दो ही दलों को चुनाव में उतारना व्यावहारिक दृष्टि से उचित माना गया राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव, भूटान में 2018 में आयोजित किए गए थे।।इस चुनाव के परिणामस्वरूप भूटान में द्रुक न्यामरूप त्शोंगपा (डी.एन.टी), राष्ट्रीय सभा में बहुमत के साथ विजयी रही तथा लोकतांत्रिक रूप से सरकार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, एवं डी.एन.टी के अध्यक्ष, लोतेय त्शेरिंग नए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। पूर्व प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे की सत्तारूढ़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (भूटान) मतदान के पहले दौर में तीसरे स्थान पर रही।भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरेटी पार्टी (द्रुक फुएनसुम त्शोंगपा, डी.पी.टी) और द्रुक न्यामरूप त्शोंगपा (डी.एन.टी) के बीच लड़ा गया था। डीएनटी को पहले दौर में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए थे। इस चुनाव से पूर्व, प्रधानमंत्री तोबगे की पार्टी (पी.डी.पी) के अलावा केवल द्रुक फुएनसुम त्शोंगपा (डी.पी.टी) ही ऐसी पार्टी थी, जिसका राष्ट्रीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व मौजूद था, जबकि विजयी पार्टी, डी.एन.टी, राष्ट्रीय सभा के एक भी आसन पर काबिज नहीं थी।

भूटान एवं नेपाल में दबाव समूहों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन दबाव अथवा हित समूह

अर्थ एवं व्याख्या

प्रायः सभी राज्यों में दलीय व्यवस्था के विकास के साथ–साथ अनेक दबाव या हित समूहों का विकास होने लगता है। ये हित समूह उन लोगों के औपचारिक संगठन होते है,जिनके एक या एक से अधिक हित अथवा उद्देश्य समान होते है, जो घटनाक्रम को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं विशेष रूप से, सरकार के द्वारा नीतियों के निर्धारण व कार्यान्वित करने में जिससे कि वे अपने हितों की रक्षा कर सके और उन्हें प्रोत्साहन दे सकें।

दबाव अथवा हित समूह की परिभाषा

वह ऐसा समूह होता है जो एक या अधिक मिली जुली अभिवृत्तियों के आधार पर समाज में अन्य समूहों पर उन अभिवृत्तियों में निहित व्यवहार के रूपों की स्थापना, स्थिरता या वृद्धि के लिए दावा करता है। इस अर्थ में, हित समूह एक श्रेणीगत समूह होता है, जिसमें सदस्य यह समझते है कि उनका सामान्य हित है तथा वे व्यवहार को सामान्य हित की वृद्धि के लिए निदेशित करते है। जब औद्योगिक व्यवसायी, वाणिज्यिक तथा समुदाय के अन्य समूह जिनका प्रतिनिधित्व अन्य व्यावसायिक संघ करते हो, वे विधान मंडल को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि वे अपने हितों में कानून बनवा सके अथवा अपने हितों को हानि पहुंचाने वाले विधेयकों को वापस लेने या उन्हें हटाने के लिए अथवा उनमें आवश्यक परिवर्तन कराने के लिए प्रयत्न कर सके। ऐसे समूहों को सामान्य बोलचाल की भाषा में दबाव समूह कहते हैं। वस्तुतरू इन दबाव समूहों के विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आवश्यक तत्व समझा जाता है।

राजनीतिक दल तथा दबाव समूह में अन्तर

किसी भी राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन में राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों दोनों की अपनी–अपनी भूमिकायें होती है। परन्तु राजनीतिक दल तथा दवाव समूह के बीच कुछ समानता तथा कुछ भिन्नता होती है। सामान्यतया राजनीतिक दल दबाव समूह से बहुत अधिक बड़ा संगठन होता है जो देश के मतदाताओं का समर्थन पाने का प्रयास करता है। परिणामस्वरूप राजनीतिक दल का कार्यक्रम विस्तृत होता है तथा उसका सम्बन्ध अनेक समस्याओं व प्रश्नों से होता है। इसके विपरीत दबाव अथवा हित समूह आकार तथा सदस्यता की दृष्टि से लघु होते है तथा वे एक ही समूह के हितो आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते है इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल शासन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता रहता है जबकि दबाव समूह अपने समूह के हित में ही नीति निर्धारण कार्यों में रुचि लेता है। वह मुख्य विशेषता जो राजनीतिक दल या दबाव समूह के बीच अन्तर पैदा करती है, यह है कि राजनीतिक दल अपने नाम से उम्मीदवार खड़े करते है, जबकि दबाव समूह ऐसा नहीं करते हैं

दबाव समूहों की विशेषतायें

दबाव या हित समूहों की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार है –

1. आजकल प्रत्येक समाज में समूहों की संख्या काफी बड़ी है तथा उनमें से अधिकतर राजनीतिक होते हैं।
2. प्रत्येक राजनीतिक हित समूह का विरोध होता है अर्थात् कुछ अन्य समूह उसके विरोधी ध्येय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते है।
3. किसी भी जटिल समाज में राजनीतिक हित समूहों की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है अर्थात एक व्यक्ति एक से अधिक हित समूहों का सदस्य हो सकता है जबकि राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य होती है।
4. चूँकि राजनीतिक हित समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है. अतः कोई भी एक समूह किसी भी प्रश्न पर अपने सभी सदस्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं कर पाता है।

दबाव समूहों की कार्य प्रणाली

दबाव समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से अग्रलिखित तरीकों का प्रयोग करते हैं–

1. व्यापक प्रचार– वे लोकमत को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचार–साहित्य वितरण तथा सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों द्वारा व्यापक प्रचार करते हैं। जनमत और सरकार की नीति को प्रभावित करने के लिए वे प्रचार करते हैं।

2. **संगठन**– दबाव समूहों का संगठन विभिन्न प्रकार का होता है, कुछ का एकात्मक, दूसरों का संघात्मक। अधिकतर दबाव समूह लोकतांत्रिक आधार पर संगठित होते है, जिनके वार्षिक सम्मेलन होते हैं जिनमें विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं तथा वे अपनी नीति व कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं।
3. **लॉबिंग**– विधायकों को प्रभावित करने की विधि खोजी जाती है।
4. **व्यापक प्रचार**– वे लोकमत को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचार–साहित्य वितरण तथा सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों द्वारा व्यापक प्रचार करते हैं। वे सक्रिय राजनीति से अलग रहते हैं, किन्तु चुनाव अभियान आदि में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता एवं कार्यकर्ता देते हैं।
5. **हड़ताल एवं प्रदर्शन**–वे समय–समय पर प्रदर्शनों एवं हड़तालों का आयोजन करके जनमत को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं।

दबाव समूहों के विभिन्न प्रकार

दबाव समूहों में कई प्रकार के भेद होते हैं वे स्थायी तथा अस्थायी आकार में बड़े या छोटे, शक्तिशाली अथवा कमजोर हो सकते हैं एक अन्य आधार पर इन्हें आर्थिक तथा अन्य कई बड़े समूह में विभाजित किया जा सकता है नेपाल में ऐसे समूहों का महत्व पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत सीमित है तथा इनकी संख्या भी अभी बहुत थोड़ी है। सन् 1990 में प्रजातांत्रिक आन्दोलन की सफलता के उपरान्त उनके महत्व तथा संख्या दोनों में ही उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। इन दबाव या हित समूहों का नेपाल की राजनीति पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है तथा आशा है कि यह प्रभाव अब बढ़ता ही जायेगा। वस्तुतः इस समय नेपाल में धर्म, जाति, जनजाति, भाषा इत्यादि परम्परागत सामाजिक संरचनाओं पर आधारित दबाव या हित समूहों के अतिरिक्त आधुनिक केन्द्रों यथा उद्योगों तथा विश्वविद्यालयों से उत्पन्न दबाव समूह उभरे है। व्यवसायी हितों ने आधुनिक ढंग के समूहों का निर्माण किया है, जिनमें सबसे बड़ा नेपाली वाणिज्य एवं उद्योग संघ है।

नेपाल में तीन प्रकार के दबाव समूह उभर रहे हैं, जिनका विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है

1. **विशेष हित संगठन**– जो अभी हाल में विकसित हुए है। ये सामाजिक एवं आर्थिक संघों के आधुनिक आकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उदाहरणार्थ ट्रेड यूनियने, व्यवसायिक समूह, सामाजिक कल्याण अभिकरण जैसे युवा एवं महिला संगठन इत्यादि।
2. ऐसे संगठन जो परम्परागत सामाजिक सम्बन्धों जाति या धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं–जैसे नेपाल राष्ट्रीय दलित जनमंच, सनातन धर्म सेवा समिति इत्यादि।
3. ऐसे संगठन जो राजनीतिक दर्शन या विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे नेपाल प्रगतिशील छात्र संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ।

जबकि भूटान की राजनीति में दबाव समूहों का नेपाल की तुलना में प्रभाव कम है, लेकिन भूटान में भी वर्तमान में कुछ राजनीतिक दबाव समूह कार्यरत है जिनका उद्देश्य जनता के हितों के लिए राजनीति को प्रभावित करना है।

भूटान में राजनीतिक दबाव समूह और नेताः

1. द्रुक नेशनल कांग्रेस या DNC
2- संयुक्त मोर्चा फॉर डेमोक्रेसी या UFD
3. संयुक्त मोर्चा फॉर डेमोक्रेसी अगेंस्ट डिक्टिटोरशिप या UDD ख्जटुप्रोन अध्यक्ष,

अन्य राजनीतिक दबाव समूहः बौद्ध पादरी, जातीय नेपाली–भूटानी संगठन राजनीतिक, सामाजिक, श्रम या धार्मिक संगठनों की सूची शामिल है जो राजनीति में शामिल हैं, या जो राजनीतिक दबाव डालते हैं, लेकिन जिनके नेता विधायी चुनाव के लिए खड़े नहीं होते हैं।

निष्कर्ष

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नेपाल व भूटान की राजनीति में अभी तक साम्प्रदायिक व जाति आधारित हित समूह या संगठनों का पूर्ण अभाव है। ऐसा नहीं है कि चुनावों में विभिन्न पार्टियों ने जाति तत्व को वरीयता नहीं दी है, बल्कि

जातियाँ पृथक राजनीतिक दल के निर्माण का आधार नहीं बन सकी है। निःसन्देह रूप से यह एक स्वस्थ परम्परा है। वास्तव में यदि देखा जाये तो नेपाल व भूटान के इन उदीयमान दबाव या हित समूहों का उद्देश्य लोकशक्ति अर्थात् जनता की शक्ति को बढ़ाना है। एक प्रकार से ये सभी समूह अपने उद्देश्यों में तो राजनीतिक पदों से दूर रहकर ही अपना कार्य करना चाहते हैं।

संदर्भ:

1. बराल, लोक राज : ***नेपाल प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस,*** कोणार्क पब्लिशर्स, दिल्ली, 1993.
2. सिंह, एस.बी. : ***इम्पैक्ट ऑफ इण्डियन नेशनल मूवमेन्ट ऑन दी पॉलिटिकल डवलपमेट इन नेपाल***, नई दिल्ली, 1985.
3. सिंह, धर्मपाल : ***भारत नेपाल संबंध संवाद की राजनीति***, गौतम बुक कंपनी पब्लिशर्स, जयपुर, 2012.
4. रॉयल गर्वनमेण्ट ऑफ भूटान, डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्फोरमेशन ऐंटीनेशनल एक्टीविटीज इन सदर्न भूटान (थिंफू, डिपार्टमेण्ट ऑफ इन्फोरमेशन, सितम्बर,1991)
5. भूटान का संविधान–प्रकाशित 26 मार्च, 2005 (भूटान सरकार द्वारा प्रकाशित)